

पूर्वव्यापी कराधान को दूर करना

प्रलिस के लिये

आयकर अधिनियम, ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय

मेन्स के लिये

पूर्वव्यापी कराधान व्यवस्था और वोडाफोन कर विवाद, नए वधियक में प्रस्तावति परविरतन एवं इसका महत्त्व

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार ने लोकसभा में **कराधान कानून (संशोधन) वधियक, 2021** पेश किया है।

- यह वधियक भारतीय संपत्ति के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने हेतु **2012 के पूर्वव्यापी कानून का उपयोग करके की गई कर की मांगों** को वापस लेने का प्रयास करता है।

प्रमुख बिंदु

पृष्ठभूमि:

- यूएस-आधारति वोडाफोन** के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद वर्ष **2012** में पूर्वव्यापी कर कानून पारति किया गया था।
 - वोडाफोन समूह की डच शाखा ने वर्ष 2007 में एक केमैन (Cayman) आइलैंड्स-आधारति कंपनी खरीदी, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय फर्म हचिसन एस्सार लिमिटेड (Hutchison Essar Ltd) में बहुमत हस्सेदारी रखी, बाद में इसका नाम बदलकर वोडाफोन इंडिया (11 बलियन डॉलर में) कर दिया गया।
- इसे वतित अधिनियम में संशोधन के बाद पेश किया गया था, जिसने कर वभिाग को सौदों के लिये पूर्वव्यापी पूंजीगत लाभ कर लगाने में सक्षम बनाया, **1962 के पश्चात् से इसमें भारत में स्थति वदिशी संस्थाओं में शेयरों का हस्तांतरण** भी शामिल है।
- जबकि संशोधन का उद्देश्य वोडाफोन को दंडति करना था, कई अन्य कंपनियों एक दूसरे के अंतरवरीध (Crossfire) में फँस गईं और वर्षों से भारत के लिये कई समस्याएँ उत्पन्न कर रही हैं।
 - यह आयकर कानून में सर्वाधिक विवादास्पद संशोधनों में से एक है।
- पछिले वर्ष भारत ने हेग में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में **केयर्न एनर्जी पीएलसी और केयर्न यूके होल्डिंग्स लिमिटेड (Cairn Energy Plc and Cairn UK holdings Ltd)** पर कंपनी द्वारा प्राप्त किये गए कथति पूंजीगत लाभ पर कर लगाने के खिलाफ एक मामले को तब खारजि कर दिया था, जब वर्ष 2006 में उसने स्थानीय इकाई को सूचीबद्ध करने से पहले देश में अपने व्यवसाय को पुनर्गठति किया था।

वधियक में प्रस्तावति परविरतन:

- आयकर अधिनियम और वतित अधिनियम, 2012 में संशोधन प्रभावी रूप से यह दर्शाता है कथदि लेन-देन 28 मई, 2012 से पहले किया गया था तो भारतीय संपत्ति के कसि भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिये कोई कर मांग नहीं की जाएगी।
- मई 2012 से पूर्व भारतीय संपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिये **लगाया गया कर "नरिदषिट शर्तों की पूर्तापर शून्य"** होगा, जैसे- लंबति मुकदमे की वापसी तथा एक उपक्रम के कोई नुकसान का दावा दायर नहीं किया जाएगा।
- यह इन मामलों में **फँसे कंपनियों द्वारा भुगतान की गई राशा को बनिा ब्याज** के वापस करने का भी प्रस्ताव करता है।

CONDITIONS APPLY

The new bill says tax claims made on offshore transactions executed prior to 28 May 2012 will be nullified, subject to riders. The status of such demands at a glance:

Status of retrospective tax demands



Arbitration awards (in ₹ crore)

Tax demanded	Arbitration
Cairn Energy Plc 10,400*	12,600 including interest
Vodafone Group Plc 19,000*	40 in costs**

*plus an equal amount in penalty, accrued interest
* updated demand in 2017
** plus ₹45 crore tax refund if award is not contested. India has appealed the award.

Source: Mint Research

LEGISLATIVE CHANGE

MOVE will help close past disputes, avoid future litigation costs

THE govt proposes to refund only the principal, not interest

SARVESH KUMAR SHARMA/MINT

वधियक का महत्त्व:

- यह वधियक बेहतर कर स्पष्टता के लिये पूर्वव्यापी कर को हटाने की मांग करने वाले वदेशी नविशकों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने की दशा में उठाया गया एक कदम है।
- यह एक नविश-अनुकूलित व्यवसायिक वातावरण स्थापित करने में मदद करेगा, जो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकता है तथा सरकार के लिये समय के साथ अधिक राजस्व संग्रहण करने में मदद करेगा।
- यह भारत की प्रतिष्ठा को बहाल करने और [ईज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस](#) में सुधार करने में मदद कर सकता है।

पूर्वव्यापी कराधान

- यह किसी भी देश को कुछ उत्पादों, वस्तुओं या सेवाओं पर कर लगाने को लेकर एक नियम पारित करने की अनुमति देता है। यह किसी भी कानून के पारित होने की तारीख की पूर्व अवधि से कंपनियों से शुल्क लेता है।
- वे देश अपनी कराधान नीतियों में किसी भी वसिगत को ठीक करने के लिये इस मार्ग का उपयोग करते हैं, जिनोंने अतीत में कंपनियों को इस तरह की खामियों का फायदा उठाने की अनुमति दी थी।
- पूर्वव्यापी कराधान उन कंपनियों को आहत करता है जिनोंने जान-बूझकर या अनजाने में कर नियमों की अलग-अलग व्याख्या की थी।
- भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड और बेलजियम, ऑस्ट्रेलिया एवं इटली सहित कई देशों में पूर्वव्यापी कराधान वाली कंपनियों हैं।

पूंजी लाभ

- यह वृद्धि या लाभ 'आय' की श्रेणी में आता है।
- इसलिये उस वर्ष में उस राशि के लिये पूंजीगत लाभ कर का भुगतान करना आवश्यक होगा जिसमें पूंजीगत संपत्तिका हस्तांतरण होता है। इसे पूंजीगत लाभ कर कहा जाता है, जो अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो सकता है।
 - दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर:** यह एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई संपत्तिका बिक्री से होने वाले मुनाफे पर लगाया जाता है। कर देने वाले वर्गों (Tax Bracket) के आधार पर ये दरें 0%, 15% या 20% हैं।
 - लघु अवधि पूंजीगत लाभ कर:** यह एक वर्ष या उससे कम समय के लिये रखी गई संपत्ति पर लागू होता है और सामान्य आय के रूप में कर लगाया जाता है।
- पूंजीगत हानियों को घटाकर पूंजीगत लाभ को कम किया जा सकता है, जो तब होता है जब एक कर योग्य संपत्तिका मूल खरीद मूल्य से कम पर बेचा जाता है। कुल पूंजीगत लाभ में से किसी भी पूंजीगत हानिको घटाकर "शुद्ध पूंजीगत लाभ" के रूप में जाना जाता है।
- पूंजीगत परसंपत्तिका संपत्तिका महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं जैसे कि घर, कार, नविश संपत्तियाँ, स्टॉक, बॉण्ड और यहाँ तक कि संग्रहणता (Collectibles) या कला।

आगे की राह

- ववादों को अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में जाने से रोकने हेतु और लागत तथा समय बचाने के लिये भारत को सीमा पार लेन-देन के मामले में सार्थक एवं स्पष्ट ववाद समाधान तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है।

- [मध्यस्थता पारस्थितिकी तंत्र](#) में सुधार से व्यापार करने में आसानी के साथ ही इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/doing-away-with-retrospective-taxation>

